



## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में  
बदलाव की आवश्यकता

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में बदलाव की आवश्यकता

### संदर्भ

- भारत का वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़ा है। हालांकि सुधार जारी हैं, फिर भी कुछ संरचनात्मक समस्याएँ बनी हुई हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है।

### भारत के वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख संरचनात्मक समस्याएँ

- **BFSI में असंगत नामांकन नियम:** बैंकों, म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों में कोई समानता नहीं।
  - विभिन्न नामांकन स्वरूपों के कारण कानूनी अस्पष्टता और मुकदमों में वृद्धि।
  - नामांकित व्यक्ति के अधिकार बनाम कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकारों में स्पष्टता की कमी।
- **कमजोर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार:**
  - नीतिगत घोषणाओं के बावजूद, भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कमजोर, तरलता-विहीन और अपारदर्शी बना हुआ है।
  - इससे व्यवसायों की पूँजी लागत 2-3% तक बढ़ जाती है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार प्रभावित होता है।
  - RBI ने NSE को द्वितीयक बॉन्ड बाजार विकसित करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे अनदेखा किया गया, संभवतः इक्विटी ट्रेडिंग में अधिक लाभ के कारण।
- **कमजोर अंतिम लाभकारी स्वामित्व (UBO) ढाँचा:**
  - भारत FATF का सदस्य है, लेकिन UBO पारदर्शिता कमजोर बनी हुई है।
- **शैडो बैंकिंग (Shadow Banking):**
  - NBFCs, मध्यस्थ और मार्जिन ऋणदाता बिना पूर्ण विनियमन के बैंकिंग सेवाओं का अनुकरण करते हैं।
  - वे 20% से अधिक प्रभावी ब्याज दर पर मार्जिन फंडिंग की पेशकश करते हैं, जिसे कई उधारकर्ता स्पष्ट रूप से नहीं समझते।
  - RBI ने 2022 में पैमाने-आधारित विनियमन लागू किया, लेकिन डेटा संग्रह और पारदर्शिता कमजोर बनी हुई है।
- **विखंडित वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण:**
  - अमेरिका के “उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (CFPB)” की तरह कोई एकीकृत वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नहीं।
  - निवेशकों/बचतकर्ताओं को SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA के बीच शिकायत निवारण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन और साइबर जोखिम:**
  - UPI ने डिजिटल वित्त में क्रांति ला दी, लेकिन डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी भी बढ़ी।
  - RBI ने FY23 में 13,530 धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्ट की, जिसमें ₹30,252 करोड़ शामिल थे।
  - कई ग्रामीण निवेशक अभी भी म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और बीमा से डिजिटल रूप से वंचित हैं।

## सरकारी पहल और सुधार

- **बैंकिंग सुधार:**
  - EASE 2.0 और EASE 3.0 (Enhanced Access and Service Excellence) जैसे सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिचालन दक्षता, ऋण वितरण और ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किए गए।
- **कॉरपोरेट बॉन्ड:**
  - बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और ऋण बाजार को गहरा करने के लिए, सरकार ने SIDBI के माध्यम से “ऋण संवर्धन योजना” लॉन्च की, जिसका उद्देश्य कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग में सुधार कर निवेशकों को आकर्षित करना है।
  - BSE Bond प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बॉन्ड जारी करने और व्यापार सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।
  - SEBI ने नियम लागू किए कि बड़े कॉरपोरेट्स को कम से कम 25% उधारी बॉन्ड्स के माध्यम से लेनी चाहिए।
- **पेंशन वित्त:**
  - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), अटल पेंशन योजना (APY) और PFRDA द्वारा प्रस्तावित पेंशन सुधार।
  - PFRDA वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक वैधानिक नियामक निकाय है।
- **नामांकन:**
  - SEBI ने 2024 में अनिवार्य नामांकन या ऑफ्ट-आउट घोषणा का परिपत्र जारी किया ताकि डिमैट और म्यूचुअल फंड खातों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- **शैडो बैंकिंग:**
  - RBI ने NBFCs के लिए 2022 में पैमाने-आधारित नियामक ढाँचा लागू किया।
  - उच्च-जोखिम वाली NBFCs पर कड़ी कार्रवाई की गई।

## आगे की राह

- **BFSI में नामांकन नियमों को एकीकृत करना:**
  - सभी वित्तीय उपकरणों के लिए एक समान नामांकन कानून।
  - कानून में स्पष्ट विभाजन कि “नामांकित व्यक्ति” एक ट्रस्टी है, जबकि “कानूनी उत्तराधिकारी” वास्तविक लाभार्थी।
- **बॉन्ड बाजार को गहरा करना:**
  - कॉरपोरेट्स को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - मार्केट-मेकर्स विकसित करें और क्रेडिट रेटिंग की पारदर्शिता बढ़ाना।
  - RBI/NSE/BSE के सहयोग से खुदरा निवेशकों के लिए अनुकूल बॉन्ड प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- **UBO प्रकटीकरण और FATF अनुपालन को मजबूत करना:**
  - संवेदनशील क्षेत्रों में UBO प्रकटीकरण की सीमा 5% या यहाँ तक कि 1% तक कम करना।
  - गैर-प्रकटीकरण और विलंबित रिपोर्टिंग के लिए सख्त दंड लागू करना।
- **कम लागत वाले पेंशन उत्पाद सक्षम करना:**
  - 30+ वर्षों के शून्य-कूपन सरकारी बॉन्ड ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से जारी करना।

- NPS को UPI-आधारित ऑटो-डेबिट सिस्टम के साथ एकीकृत करना ताकि अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सुविधा हो।
- छाया बैंकिंग को नियंत्रित करें:
  - मार्जिन लेंडिंग और NBFC लेन-देन पर व्यापक डेटा संग्रह अनिवार्य करना।
  - NBFC ऋण को RBI के “CRILC” (क्रेडिट सूचना प्लेटफॉर्म) डेटाबेस में एकीकृत करना।
  - वित्तीय दलालों के लिए जोखिम-आधारित पूँजी मानदंड लागू करना

Source: TH

### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** भारत के अविकसित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और अपारदर्शी अंतिम लाभकारी स्वामित्व (UBO) मानदंडों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की जाँच कीजिए।

■■■■

